>

Title : Need to address the problems being faced by Madarsa teachers in the country.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सदन का ध्यान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एसपीक्यूईएम, यानी स्पेशल प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज, की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 5445 मदरसों के 14028 शिक्षकों को, जो पिछले दो साल से कार्यरत् हैं, उनका वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 की मानदेय धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है। इसके कारण मदरसा आधुनिक शिक्षकों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। टीचर्स एसोसियेशन ने कई बार सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है

टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2011 को दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें हजारों की संख्या में मदरसा टीचर्स मौजूद थे, जिसमें उनकी मांगों के सहयोग के लिए मैं भी उपस्थित था, चौधरी लाल सिंह जी भी वहां मौजूद थे, अन्य कई सांसद भी वहां गए थे, इसमें उनकी प्रमुख मांग थी कि मदरसा आधुनिक शिक्षा योजना को स्थायी किया जाए। आधुनिक शिक्षा योजना का बजट बढ़ाया जाए। योजना में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 5445 मदरसों के 14025 शिक्षकों का वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11, दो वर्षों का बकाया मानदेय भुगतान धनराशि उत्तर प्रदेश को दी जाए। योजना में एम.ए., बी.ए. एवं बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए। योजना में कार्यरत शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाई जाए तथा योजना में आधुनिक शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाए। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मदरसा शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की कृपा करें ताकि वे अपनी जरूरी मांगों की पूर्ति के लिए आन्दोलन करने के बजाय अपना समय बच्चों को शिक्षित कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें।